भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-7

उत्तर देने की तारीख-**21/07/2025**

डिजिटल लर्निंग

†7. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु सहित देश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग शुरू करने का कोई दृष्टिकोण या योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस दिशा में किस हद तक आगे बढ़ने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) (पैरा 4.23) में उल्लिखित है कि कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सभी छात्रों द्वारा सीखा जाना चाहिए, जिसमें डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटर आधारित सोच शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जिसके तहत तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में शिक्षा के लिए एक से अधिक मोड में पहुँच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। पीएम ई-विद्या पहल को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से सहायता प्राप्त होती है और इसे एनसीईआरटी के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। इन पहलों के घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकतानुसार डिजिटल शिक्षा सहित इन पहलों का प्रभावकारी उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने हेतु एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर नियमित प्रतिक्रिया देती है।

पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में भी अनुकूलित हैं और इसमें शामिल हैं:

- डीटीएच टीवी चैनल : इन चैनलों का प्रारंभ 9 मार्च 2024 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों का विस्तार 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक कर दिया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। ये चैनल एनसीईआरटी के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र और स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं और कार्यरत हैं। तमिलनाडु राज्य को तमिल/स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए 5 चैनल (चैनल संख्या 158 से 162) आवंटित किए गए हैं, हालांकि राज्य ने इन आवंटित चैनलों का उपयोग करने के लिए एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना अभी बाकी है।

भारतीय भाषाओं के अधिगम को सुविधागत बनाने के लिए पीएम ई-विद्या पहल (चैनल सं. 34) के एक भाग के रूप में समर्पित तमिल भाषा का एक टीवी चैनल 29 जुलाई, 2024 को शुरू किया गया है। इसके अलावा, 6 दिसंबर 2024 को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को बढ़ावा देने हेतु एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुरूप और आवश्यक

दर्शकों तक आईएसएल में शिक्षण सामग्री की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, माननीय शिक्षा मंत्री ने एक समर्पित पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल (चैनल सं.31) के माध्यम से श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक समर्पित पहल शुरू की। डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेज़ी) और एनसीईआरटी/एनआईओएस वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर सांकेतिक भाषा में दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों के लिए विशेष ई-सामग्री विकसित की गई।

एनसीईआरटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने हेतु डीटीएच चैनलों और यूट्यूब पर प्रतिदिन डिजिटल साक्षरता की एक घंटे की सामग्री प्रसारित की जाती है।

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली प्रेरक पाठ्यपुस्तकें (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) उपलब्ध कराने हेतु देश का डिजिटल अवसंरचना दीक्षा (दीक्षा) है। छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर कुल 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल हैं।

एनईपी 2020 की सिफ़ारिशों के अनुरूप, युवा शिक्षार्थियों और वयस्कों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 117 भारतीय भाषा प्राइमर जारी किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु के लिए तमिल प्राइमर भी शामिल है।

महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता का महत्व देने के लिए, 300 से अधिक वर्चुअल लैब बनाए गए हैं और उन्हें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय, तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहलों को लागू करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन पहलों के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकतानुसार आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा स्थापित करने हेतु निधि प्रदान की जाती है। आईसीटी योजना में दो विकल्प शामिल है:

1. **विकल्प I:** जिन स्कूलों के पास पहले से आईसीटी सुविधाएँ नहीं हैं, वे आईसीटी लैब या स्मार्ट कक्षा चुन सकते हैं। 700 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूलों को एक अतिरिक्त आईसीटी लैब मिल सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधन, डिजिटल बोर्ड, आभासी कक्षा और डीटीएच चैनल खरीद सकते हैं।
2. **विकल्प II:** मौजूदा आईसीटी सुविधाओं वाले स्कूल योजना संबंधी मानदंडों के तहत स्मार्ट कक्षाओं या टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं।

तमिलनाडु में आईसीटी कवरेज:

1. सभी सरकारी मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं - जिनमें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6,995 स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 6,223 स्कूल शामिल हैं।
2. राज्य निधि के माध्यम से 22,066 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट कक्षा स्थापित किए गए हैं।
3. शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निधि के तहत स्वीकृत 865 सरकारी उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी स्मार्ट कक्षा स्थापित किए गए हैं।
4. सभी 6,995 माध्यमिक विद्यालयों और सभी 6,223 हाई उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अलावा, 21,350 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

*****